नीति का मुख्य सिद्धांत सबको शिक्षा उपलब्ध कराना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुल जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत भाग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है और और उन्हें शिक्षित करने की अत्यधिक आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या विशेष व्यवस्था की गई है ; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन0पी0ई0) 1986 में संकल्प व्यक्त किया गया है कि इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने से पहले 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को संतोषजनक कोटि की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 1991–92 के अनुसार वर्ष 1997–98 में जनसंख्या का 29.9 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है ।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब तक समान अवसरों से वंचित वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके असमानता दूर करके तथा शैक्षिक अवसरों को समान बनाने पर विशेष बल दिया गया है । इसके लिए औपचारिक स्कूल प्रणाली, अनौपचारिक शिक्षा स्कीम तथा प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को शिक्षित बनाया जा रहा है ।

(घ) आठवीं योजना में प्रारंभिक शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्य है ---

पहुंच

(i) अ०जा०/अ०ज०जा० की लड़कियों और व्यक्तियों सहित सभी बच्चों का सर्वसुलभ दाखिला ;

(ii) एक किलोमीटर की पैदल दूरी के क्षेत्र के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल का प्रावधान तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों और कामगार बच्चों तथा लड़कियों जो स्कूल नहीं जा सकती के लिए गैर औपचारिक शिक्षा की की सुविधा ;

(iii) अपर प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों के वर्तमान अनुपात को 1:4 से 1:2 तक बढ़ाना, क्योंकि यह अपर प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए व्यापक अवसर की पूर्व शर्त है ;

सहभागिता

(iv) कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 में स्कूल छोड़ने वाले के वर्तमान प्रतिशत को 46 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से कम करके क्रमशः 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत करना ।

उपलब्धि

(v) प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चों द्वारा सीखने के न्यूनतम स्तरों की प्राप्ति तथा अपर प्राथमिक स्तर पर व्यापक पैमाने पर इस संकल्पना को लागू करना ।

नवोदय विद्यालय में प्रति छात्र खर्च

1705. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालयों की स्थापना के समय प्रति छात्र कितना खर्च होने का अनुमान था ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रति छात्र खर्च में संशोधन नहीं किया गया है यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार खर्च में वृद्धि करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके

क्या कारण हैं, और यदि हां, तो खर्च में प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (कुमारी शलजा): (क) से (ग) वर्ष 1986-87 के दौरान, नवोदय विद्यालय समिति में प्रति छात्र खर्च, 10,870/- रुपये था। छात्रों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ, प्रति छात्र ऊपरी खर्च, स्वभाविक रूप से कम हो गया था और वर्ष 1990-91 में, प्रति छात्र व्यय खर्च 7474 रुपय था। तथापि, वर्ष 1992-93 के लिए, भोजन तथा, अन्य व्यक्तिक आपूर्तियों पर प्रति छात्र व्यय, संशोधित कर दिया गया है और पहले के 3500/- रुपय के मुकाबले में 5000/- रुपए तक वार्षिक होगा।

Parallel Grant Commission for Classical Languages

1706. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have cleared a proposal to set up a parallel Grants Commission for Sanskrit and other classical languages; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA): (a) and (b) The Government has decided in principle to set-up autonomous Commission to foster and improve teaching, study and research in Sanskrit and other Classical Languages. However, the details thereof have not yet been finalised.

Jaugada Fort in Orissa

1707. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Rock Edicts of the Jaugada Fort a historic monument of around 260 B.C. in Orissa are facing serious threats to their existence;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government propose to take in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA): (a) No Sir. The Ashoka Rock Edict at Jaugada in Pandaya is not facing any threat to its existence.

(b) Does not arise.

(c) The following steps have already been taken for its conservation:—

(i) The rock edict has been covered with a pillared mandapa to protect it from sun and rain.

(ii) Chemical treatment and pre-

(iii) A Mild steel grill has been provided to prevent visitors from touching the inscription.

(iv) The area is partly fenced for better security.

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम

1708. **श्री महेश्वर सिंह**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान भी देश के कुछ खंडों में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है

(ख) यदि हां तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और